उत्तर प्रदेश में शिक्षा परियोजनाओं का पुनरीक्षण

*171. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा परियोजनाओं के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका समग्र सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत और अधिक जिलों को शामिल करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) महिला समाख्या और तकनीकी शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में लागू की जा रही है । इन दोनों परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है ।

(ख) संयुक्त भारत-डच पुनरीक्षा मिशन, जिसने नवम्बर, 1991 में महिला समाख्या परियोजना की पुनरीक्षा की थी, यह निष्कर्ष निकाला था कि जिला स्तर पर अच्छा काम हो रहा है और इसमें शामिल किए गए जिलों में महिला जागरूकता बढ़ रही है ।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा परियोजना की समय-समय पर भारत सरकार और विश्व बैंक पुनरीक्षा मिशन द्वारा पुनरीक्षा की जाती है । इन पुनरीक्षाओं से पता चलता है कि इस परियोजना का उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है ।

(ग) चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश में महिला समाख्या परियोजना के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश के अनुमोदित/मान्यता प्राप्त सभी पॉलिटेकनिकों को तकनीकी शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पहले ही शामिल कर लिया गया है ।

प्राथमिक शिक्षा संबंधी नवीकरण योजना

*172. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कोई नवीनीकरण योजना तैयार की है जिसे जिला-स्तर पर लागू किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को देश के सभी जिलों में लागू करने का निर्णय भी किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) कार्रवाई योजना, 1992 में वर्णित प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की मुख्य कार्यनीति में अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करने तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना को अपनाने की परिकल्पना की गई है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिला विशेष पर आधारित परियोजनाएं विकसित करके इस कार्यनीति को कार्यान्वित कर रहा है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य योजनाओं के थोड़े-थोड़े भागों को कार्यान्वित करने के बजाए चयनित जिलों में प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतया पुनर्गठित करना है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ऐसे जिलों को शामिल करने का प्रयास करता है जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा जहां संपूर्ण साक्षरता अभियानों के कारण शिक्षा के लिए सार्थक

मांग उत्पन्न हो गई है। 1993–94 से शुरू करके इस प्रकार के सभी जिलों को अंततः चरणबद्ध ढंग से शामिल करने का लक्ष्य है।

सरदार सरोवर परियोजना

*173. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना के लिये संवितरित न किये गए ऋण को रद्द करने के संबंध में भारत के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(ख) भारत को किन परिस्थितियों के तहत संवितरित न किये गए ऋण को रद्द करने के लिए अनुरोध करना पड़ा; और

(ग) इस प्रकार संवितरित न किये गये कितने ऋण को रद्द किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (नीचे देखिये)।

(ग) ऋण की अवितरित राशि लगभग 170 मिलियन अमरीकी डालर है।

विवरण

मई, 1985 में सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना के लिए 99.7 मिलियन एस० डी० आर० की आई० डी० ए० ऋण सहायता और 200 मिलियन अमेरिकी डालर की अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) ऋण सहायता और परियोजना की नहर प्रणाली के लिए 149.5 मिलियन एस०डी०आर० की आई०डी०ए० ऋण सहायता हेतु विश्व बैंक के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 99.7 और 149.5 मिलियन अमेरिकी डालर के एस०डी०आर० ऋणों का उपयोग जुलाई, 1992 तक पूर्ण रूप से किया गया है। 532.2 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल ऋण/क्रेडिट राशि के मुकाबले परियोजना ने फरवरी, 1993 तक कुल मिलाकर 333.666 मिलियन अमेरिकी डालर का उपयोग कर लिया है।

स्वतंत्र पुनरीक्षा रिपोर्ट के प्रकाशन और उस पर भारत सरकार के उत्तर के पश्चात् विश्व बैंक ने स्थिति की पुनरीक्षा की और 23-10-92 को परियोजना को सहायता जारी रखने का निर्णय लिया बशर्ते अप्रैल, 1993 में विशेष मिशन द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले विशिष्ट निष्पादन बेंचमार्कों को पूरा कर लिया गया हो। भारत सरकार, और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपयुक्त उपाय प्रारंभ कर दिए और उनको 5 माह के भीतर अर्थात् मार्च 1992 के अंत तक अधिकांशतः पूरा कर दिया था। तथापि, यह देखा गया कि परियोजना पर विवाद को जटिल बनाने और भारत और विदेशों में मामले को राजनीतिक रंग देने के प्रयास किए जा रहे थे। स्थानीय रूप से गड़बड़ी उत्पन्न करने के प्रयास भी किए गए, जिससे पुनर्वास और पुर्नस्थापना कार्य के कार्यान्वयन में बाधा पहुंची। वातावरण को और दूषित होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से सहायता न लेने और इस परियोजना के लिए क्रेडिट/ऋण के बकाया भाग का भुगतान नहीं लेने का निर्णय लिया।

पाठ्य पुस्तकों की मांग पूरी करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) की विफलता

*174. **श्री गुफरान आजम :**
श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1993 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "नीड टू रिव्यू प्राइवेटाइजेशन ऑफ टैक्सट